दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

3 नेपाल से 7 साल बाद सामने आई PM रिपोर्ट क्रॉस वेरीफाई कर फिर कोर्ट में होगा दाखिल

5 यूपी में एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय एक माह बढ़ा

8 सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल!

UPHIN/2023/90814 | वर्ष: 03, अंक: 33 | पृष्ठ संख्या: 8 | मूल्य: 1.00 रू. | सोमवार 09 फरवरी, 2026

CM योगी के आदेश पर 'घूसखोर पंडत' वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज

लखनऊ,संवाददाता। ब्राह्मण समाज को इस फिल्म के टाइटल पर एतराज है। वहीं, राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध को देखते हुए 'घूसखोर पंडत' वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई सीएम योगी के आदेश पर हुई है। सरकार का कहना है कि सामाजिक सौहार्द और कानून–व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित आपत्तिजनक कंटेंट पर हजरतगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर प्रसारित की जा रही है। वेब सीरीज में जातिगत भावनाएं आहत करने का आरोप है। इसके अलावा वैमनस्य फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सामग्री प्रसारण का भी आरोप है।

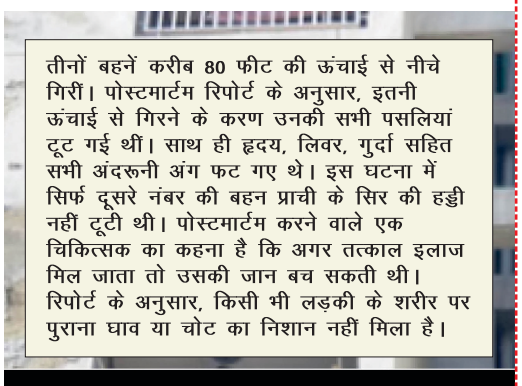

तीन बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 80 फीट से गिरीं, टूटीं सभी पसलियां, लिवर-गुर्दा और दिल फटे

तीनों बहनें करीब 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, इतनी ऊंचाई से गिरने के करण उनकी सभी पसलियां टूट गई थीं। साथ ही हृदय, लिवर, गुर्दा सहित सभी अंदरूनी अंग फट गए थे। इस घटना में सिर्फ दूसरे नंबर की बहन प्राची के सिर की हड्डी नहीं टूटी थी। पोस्टमार्टम करने वाले एक चिकित्सक का कहना है कि अगर तत्काल इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी लड़की के शरीर पर पुराना घाव या चोट का निशान नहीं मिला है।

लक्ष्मी भंडार योजना.. इस स्कीम से ममता हर बार रोक देती हैं BJP का रथ!

लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र बनी हुई है, जिसने 2021 से 2026 तक के चुनावी नैरेटिव को जोड़ दिया है. ममता बनर्जी सरकार द्वारा अंतरिम बजट में राशि बढ़ाने के ऐलान और विपक्षी वादों के बावजूद, यह योजना महिला वोट बैंक पर तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ को दिखाती है. राज्य में महिलाओं का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है और लक्ष्मी भंडार व कन्याश्री जैसी योजनाओं ने इस वर्ग को सीधे प्रभावित किया है।

अंडर–19 चैंपियंस

दिल्ली,एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर–19 वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला गया। भारत ने 411 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड को 311 रन पर समेट दिया। यह टीम इंडिया का छठा अंडर–19 विश्व कप खिताब है।

भारत ने अंडर–19 विश्वकप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। यह टीम इंडिया का रिकॉर्ड छठा खिताब है। इससे पहले भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर–19 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत ने इंग्लैंड के सामने 412 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में 311 रन रन पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी फाइनल के सुपरस्टार रहे। उन्होंने 80 गेंद में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं, इंग्लैंड की ओर से कैलब फाल्कनर ने शतक जड़ा, लेकिन टीम को नहीं जिता पाए। फाल्कनर ने 67 गेंद पर 115 रन की पारी खेली।

भारत छठी बार अंडर-19 विश्वकप चैंपियन

वर्तमान हमारा, भविष्य हमारा, कीर्तिमान हमारा है

रिकॉर्ड स्कोर के बाद रनों से सबसे बड़ी जीत! भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 विश्वकप का खिताब

सवा तीन करोड़ मतदाताओं को मिलेगा चुनाव आयोग का नोटिस 6 मार्च तक दे सकेंगे जवाब, उम्र को लेकर समस्याए

यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया एक महीने और बढ़ा दी गई है। अब 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

लखनऊ,संवाददाता। प्रदेश में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा 6 मार्च तक बढ़ा दी है। अभी दावे और आपत्तियों के लिए 6 फरवरी अंतिम तारीख थी। इसके अलावा मैपिंग से जुड़े सभी नोटिसों की प्रक्रिया 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च तक पूरी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। लोकभवन में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में बताया कि फार्म–6 के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैपिंग को लेकर भारी संख्या में नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस और फार्म की भारी संख्या की वजह से समय बढ़ाने की मांग राजनीतिक दलों ने की थी।

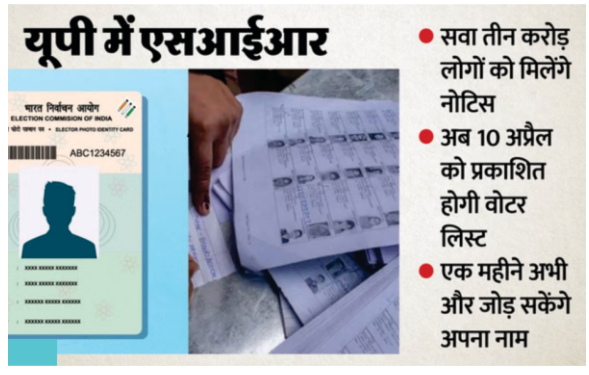

जालसाजी से कमाए आईएएस के रुपयों को रजिस्ट्री में खपाते थे, गिरफ्तार

गोरखपुर,संवाददाता। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार रामनयन गुप्ता ठगी की रकम से अब तक करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीद चुका है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 100 डिसमिल से अधिक जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई है। जालसाजी से प्राप्त रकम सीधे काश्तकार के खाते में भेजी जाती थी और बाद में जमीन का बैनामा रामनयन गुप्ता के नाम करा लिया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी संग पुलिस

सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी फर्जी आईएएस ललित किशोर के एक और साथी को गुलरिहा पुलिस ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के गिरमिट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर निवासी रामनयन गुप्ता के रूप में हुई है।

फर्जी आईएएस गौरव कुमार सिंह

पुलिस के मुताबिक, रामनयन फर्जी आईएएस के हड़पे गए रुपये से अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराता था। दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। गोरखपुर स्टेशन पर बिहार के पटना निवासी व्यापारी मुकुंद माधव को करीब एक करोड़ रुपये नकद के साथ पकड़ा गया था। व्यापारी ने सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया।

भूकंप के झटकों से हिला गोंडा, 3.7 रही तीव्रता

गौरव का क्षण
भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को मिला 'ग्लोबल टीचर प्राइज'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील का नया फॉर्मूला तैयार

सम्पादकीय

बन गई बिगड़ी बात भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल

अच्छा हो कि इस समझौते को अंतिम रूप देते समय अमेरिका को यह संदेश दे दिया जाए कि उसने पिछले छह माह में भारत से जैसा व्यवहार किया, उसके चलते उस पर भरोसा डिगा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को 18 प्रतिशत किए जाने की घोषणा और उसका भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से स्वागत करने से यह स्पष्ट हो गया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को यह आभास हो गया कि भारत उनके अनुचित दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने भारत को दबाव में लेने के लिए तमाम जतन किए, लेकिन वे इसलिए नाकाम रहे, क्योंकि भारत ने उनसे उलझने के स्थान पर संयम और दृढ़ता का परिचय दिया।

18 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि भारत अमेरिका से व्यापार के मामले में अपने कई प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 25 से 18 प्रतिशत तो किया ही, रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को पूरी तरह हटाया भी। उन्होंने इसी के साथ यह भी कहा कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और रूस से तेल आयात बंद करेगा।

उनकी इस घोषणा के पहले भारतीय प्रधानमंत्री की वेनेजुएला की राष्ट्रपति से बात हुई थी। शायद इसके बाद ही अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर बिगड़ी बात बनी। यदि भारत को उचित मूल्य पर वेनेजुएला से तेल मिलता है तो इसमें हर्ज नहीं। आखिर वह पहले भी उसके साथ–साथ ईरान से तेल खरीदता ही था।

भारत के लिए यह संभव नहीं था कि वह रूस से तेल खरीद का विकल्प मिले बिना उससे तेल लेना बंद कर देता। देखना है कि भारत को उतना तेल वेनेजुएला से मिल पाता है या नहीं, जितना वह रूस से लेता था? इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी सामने आना शेष है कि क्या भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करना होगा और क्या अमेरिका से 500 अरब डालर की खरीद करनी होगी, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं।

वास्तव में कई सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे, जब व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन इतना तो है ही कि अमेरिका से व्यापार का जो दरवाजा बंद सा हो गया था, वह खुल गया और भारत के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा। शेयर बाजार ने इसके संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं।

चूंकि ट्रंप बढ़–चढ़कर दावा करते रहते हैं, इसलिए यह मानकर चला जाना चाहिए कि अमेरिका से व्यापार समझौता ठीक वैसा नहीं होगा, जैसा वे कह रहे हैं। इसका संकेत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस कथन से मिलता है कि भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर व्यापार समझौता करने जा रहा है। अच्छा हो कि इस समझौते को अंतिम रूप देते समय अमेरिका को यह संदेश दे दिया जाए कि उसने पिछले छह माह में भारत से जैसा व्यवहार किया, उसके चलते उस पर भरोसा डिगा है।

असामान्य वित्तीय हालात

जिस वित्तायोग के सहारे पर्वतीय धमनियों को आर्थिक आक्सीजन मिलती थी, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने ऐलान करके हिमाचल को नाखून चबाने की स्थिति में ला खड़ा किया है। पंद्रहवें वित्तायोग ने पांच सालों में 49 हजार करोड़ की मदद, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी के रूप में दी, उसे पूरी तरह खत्म कर गिया गया है। अगर केंद्र हिमाचल जैसे छोटे व पर्वतीय राज्यों को वित्तीय अनुशासन सिखाना चाहता है, तो मिलकीयत में मिले अधिकारों की पहचान जरूरी है। बेशक आत्मनिर्भर होने के रास्ते हैं, लेकिन इसके लिए हिमाचल के अधिकारों से पर्दा हटना चाहिए। यह जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है, जिसका मोल–तोल होना चाहिए। बेशक राज्य की आर्थिक स्थिति व केंद्र से मिले झटके पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी आहूत करनी होगी। मसला हिमाचली अधिकारों का है, तो वो दौर भी याद करना होगा जब बतौर मुख्यमंत्री शांता कुमार केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार से मुफ्त बिजली की रॉयल्टी ले आए थे या प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्रित्व में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने औद्योगिक पैकेज देकर प्रदेश की उत्पादन क्षमता को ताकत दी थी। इसी संदर्भ में कनेक्टिविटी, रेल या पर्यटन विकास पैकेज की अपेक्षा केंद्र से रही है। विडंबना यह है कि मैदानी प्रदेशों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र के भंडार भरे नजर आते हैं, लेकिन पौंग, गोविंद सागर व अन्य जलाशयों एवं विद्युत परियोजनाओं से हिमाचल को आज भी ठेंगा मिल रहा है। न विस्थापितों का दर्द पौंछा गया और न ही केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों में इस्तेमाल होता पानी हमारे लिए आर्थिक संबल बना। ऐसे में वाटर सैस जैसे स्वावलंबी कदम को रोक के बैठी केंद्र सरकार आखिर तोल क्या रही है। क्या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले राज्य को केंद्रीय बजट के आबंटन तथा वित्तीय आयोग की सिफारिशों में केवल शून्यता ही मिलेगी। अधिकार तो पंजाब पुनर्गठन के भी सड़ रहे हैं और शानन विद्युत परियोजना की मिलकीयत में भी अपमान कर रहे हैं, तो फिर इंसाफ का राष्ट्रीय चरित्र है क्या। पहले पहाड़ी लोग सेना भर्ती के अगुआ होते थे, लेकिन अब कोटे में सामर्थ्य गायब है, लिहाजा शहादत के परिंदों का आकाश छोटा करके देखा जा रहा है।

छिलकों की छाबड़ी संपर्क बिना जग सून

हमें मालूम हो गया कि उनकी धरती के इस चौड़े सीने पर हमारे जैसों को कोई जगह नहीं मिलेगी। चंद महापुरुषों से मुलाकात हुई है, जो मिलते ही हमसे चरण वंदना की उम्मीद करने लगते हैं। नहीं कर पाते, तो हमें तुरंत अपने गुट से बाहर फेंक देते हैं। हमारे खिलाफ एकतरफा जंग का ऐलान कर देते हैं, लेकिन अब जो पहले ही आपके अखाड़े में पराजित बैठा हो, उसे जंग लडने के लिए कैसे उकसाओगे? जिंदगी के कामयाबी से जीने के आपके कुछ असूल हैं, जो उम्र भर उन पर चल ही नहीं पाया, उसके खिलाफ आपने अपना फौज फांटा खड़ा भी कर लिया, तो क्या किया। जो आपके अखाड़े में उतरा ही नहीं, उसे आपके अखाड़े का भगौड़ा घोषित कर दिया, यह क्या किया? वह मूर्ख था। उसने जो किताबों में पढ़ा था, उसे ही अपनी जिंदगी में ढालने का प्रयास करता रहा, इसलिए कभी न उधर का हो सका, न इधर का। कामयाबी ने उसके कभी पग तो क्या माथा भी नहीं चूमा, और असफलता तो उसका परिचय बनी। उसके साथ कोई अतिवादी मानक डिग्रियां कैसे जोड़ देता? हमने छक्कन से पूछा, 'कि आप किस की बात कह रहे हैं, भाई साहब। कहीं हमारी और हमारे लिखने की बात तो नहीं कर रहे, जिसे कभी किसी ने पढ़ा तो है न, और लेखक मानने से हमेशा इन्कार कर दिया।' इसके बावजूद आप मरते दम तक लिखने से बाज नहीं आए। वह अवश्य आश्वस्त हो गए होंगे, कि इस जन्मजात जुनूनी का शुरू से कोई पेंच ढीला था, देख तो मरते दम तक ढीला ही रहा। उन्होंने कह दिया होगा। अपने बारे में ऐसा सुनना कुछ अजीब नहीं लगता।

हम शुरू से ही असाधारण नहीं थे, जिस काम में हाथ डालते अपनी अति–साधारणता से उसका गुड़ गोबर कर देते। अब लगता है हम अपनी जिंदगी का किस्सा बयान नहीं कर रहे। इस देश की सडक़ पर चलते हर सडक़छाप आदमी का किस्सा बयान कर रहे हैं। उसे बार–बार जो कहा जाता है, वह उस पर विश्वास कर लेता है। उसे कहा जाता है, कहा जाता रहेगा कि एक दिन तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, और वह हर बार विश्वास कर लेगा, कि हां उसके अच्छे दिन आएंगे। खेतों की फसल कटने की तरह जब वोट बटोरने का मौसम गुजर जाएगा, तो वह देखेगा जो उसके अच्छे दिन ला रहे थे, वे स्वयं अच्छे दिनों को अपने बटुए में डाल कर ले गए और उसके अच्छे दिन किसी दूर के भविष्य की तिथि के लिए स्थगित हो गए। फिलहाल जीने के लिए उसे किसी रियायती राशन के बाहर कतार लगानी पड़ेगी, और अपनी बारी के लिए मध्यस्थों की चिरौरी करनी होगी। यह मध्यस्थजन भी खूब होते हैं। साहिब जगह बदलने के साथ इनके नाम भी बदलते रहते हैं। कहीं इनके लिए सम्पर्क संस्कृति का सभ्य नाम दे दिया जाता है, और कभी इनके दलाली के धंधे को बाकायदा कानून–सम्मत ठहराने के प्रयास भी होते हैं। आज सही सम्पर्क के बिना आप कुछ भी तो नहीं, बन्धु। थाने में चोरी की रपट लिखवाने से लेकर अपने लिए कोई छोटी–मोटी नौकरी जुटाने तक के लिए सही सम्पर्क जुटाना पड़ता है। 'सम्पर्क बिना जग सून', आज के युग का नया मूल मन्त्र है। असभ्य भाषा में इसे सिफारिश और सभ्य भाषा में इसे योग्यता की पहचान कह देते हैं। योग्यता की यह पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो युगानुसार हो जाती है। हर युग का अपना–अपना तेवर है। जैसे आजकल परिवारवाद को गाली देने का युग है, तो आगे बढ़ कर परिवारवाद को भरपूर गाली दे दो, लेकिन अपनी संतान, नाती–पोतों का भविष्य सुरक्षित करके। लोगों का क्या है, वह तो मान ही जाएंगे कि हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं।

अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत, ट्रंप ने टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत किया

पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक तनाव, आपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की आशंका और अमेरिका के साथ खटपट के नाम रहा। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई बात का बनना बहुत कुछ कहता है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह मोदी की विदेश नीति की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की पुष्टि भी है। जब तमाम विश्लेषक यह मान बैठे थे कि ट्रंप 2.0 के दौर में भारत को लगातार दबाव और अपमान झेलना पड़ेगा, उसी दौरान मोदी ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को पलट दिया। यह समझौता दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है।

देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात 'द आर्ट आफ द डील' रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे। स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है। मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दर्शाता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे 'फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ। भारत–अमेरिका समझौता भी इसी श्रेणी में आता है।

इसमें तनाव घटाने, व्यापार बहाली और रणनीतिक खाई को पाटने जैसे लक्ष्य तो स्पष्ट हैं, लेकिन विवरण अभी शेष हैं। कभी–कभी कूटनीति में दिशा तय करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने विकल्प भी बढ़ाए। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, चीन के साथ सीमित राजनीतिक संवाद और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। इस क्रम में यदि वाशिंगटन भारत के साथ व्यापारिक टकराव जारी रखता तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। यही वह बिंदु है, जिसने अमेरिका को अड़ियल रुख से पीटे हटने को विवश किया। इसमें यूरोपीय संघ के साथ समझौते ने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी रुख में परिवर्तन भारत के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि उसके 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारत को एक बड़े बाजार में सीमित कर दिया था। अमेरिकी टैरिफ का 18 प्रतिशत पर आना न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए राहत है, बल्कि यह भारत को फिर से एशियाई प्रतिस्पर्धियों की पंक्ति में खड़ा करता है।

इसके चलते वस्त्र, परिधान, रत्न और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को संजीवनी मिलेगी। चीन से बाहर निकल रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत फिर से एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। उच्च टैरिफ के चलते जो अवसर भारत के हाथ से फिसल रहे थे, वे फिर से मुट्ठी में आ सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता चीन को भी यह संदेश देगी कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प हैं। हालांकि मोदी की विदेश नीति का मूल तत्व अब भी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह समझौता उस स्वायत्तता को त्यागने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का साधन है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता एक नई शुरुआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसके सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अवसर इसलिए कि यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भारत–अमेरिका संबंध वास्तव में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। चुनौतियां इसलिए कि विवरणों में मतभेद, घरेलू दबाव और ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। इसके बावजूद मोदी को श्रेय देना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है।

नेपाल से 7 साल बाद सामने आई PM रिपोर्ट क्रॉस वेरीफाई कर फिर कोर्ट में होगा दाखिल

गोरखपुर,संवाददाता । नेपाल की कास्की जिला पुलिस ने पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 देउराली शुमती स्थित थोपसे खोला सामुदायिक वन क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों के बीच सूखे पत्तों से ढका हुआ राखी का शव बरामद किया था।

इसके बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नेपाल के वेस्टर्न रीजनल हॉस्पिटल पोखरा भेजा था। नेपाल में वर्ष 2018 में शाहपुर की राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव हत्याकांड में सात साल बाद आखिरकार नेपाल से पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट गोरखपुर पुलिस के हाथ लगी है। यह रिपोर्ट क्रॉस वेरीफाई कराने के बाद कोर्ट में दाखिल कर ट्रायल शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

राखी अपने पति मनीष सिन्हा के साथ वर्ष 2018 में नेपाल भ्रमण पर गई थी। इसी दौरान नेपाल के कास्की जिले के सारंगकोट क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला था। राखी के

मायके वालों ने उसका अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने डॉ. डीपी सिंह और उनके दो कर्मचारी संतोष कुमार और देश दीपक को आरोपी बनाकर जेल भिजवाया था। पुलिस का दावा था कि हत्यारोपियों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसे पहाड़ से धक्का दे दिया था।

नेपाल की कास्की जिला पुलिस ने पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 देउराली शुमती स्थित थोपसे खोला सामुदायिक वन क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों के बीच सूखे पत्तों से ढका हुआ राखी का शव बरामद किया था। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नेपाल के वेस्टर्न रीजनल हॉस्पिटल पोखरा भेजा था।

जांच में शामिल सूत्रों के अनुसार, मृतक राखी के बड़े भाई और मुकदमा वादी अमर प्रकाश श्रीवास्तव हर साल नेपाल जाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वहां की पुलिस हमेशा क्राइम सीन, पोस्टमार्टम और आरोपी की स्थानीयता का हवाला देकर रिपोर्ट देने से इन्कार कर देती थी।

पिछले साल दिसंबर में अथक प्रयासों के बाद नेपाल पुलिस ने उन्हें रिपोर्ट सौंप दी। उनका आरोप है कि पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण डॉ. डीपी सिंह और दो कर्मचारी संतोष कुमार और देश दीपक महज चार माह में ही जमानत पर बाहर आ गए थे। इसके बाद आरोपी पक्ष ने मुकदमा खत्म करने की अपील की थी, लेकिन खारिज होने के बाद प्रोसेडिंग स्टे लगा दिया गया था। इससे केस का ट्रायल पहले शुरू नहीं हो सका।

बीते 18 दिसंबर को वादी मुकदमा ने एसएसपी से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन लिया।

अब दिल्ली मंत्रालय से क्रॉस वेरीफिकेशन की परमिशन का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद पुलिस टीम नेपाल जाएगी और रिपोर्ट की पुष्टि के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट मिलने के बाद अब अपहरण से तरमीम हत्या के मुकदमे में गिरफ्तारी और गवाहों के बयान का इस्तेमाल कर ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। वादी के अनुसार, राखी के भाई ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो बाद में हत्या में तरमीम हुई थी। पीएम रिपोर्ट और डिजिटल–भौतिक साक्ष्यों के आधार पर केस का ट्रायल जल्द ही शुरू किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।

रवि श्रीवास्तव, सीओ गोरखनाथ

किशोरी संग दुष्कर्म

पीड़िता के हाथ की नस काटने का वीडियो वायरल, इंस्टा आईडी भी सोशल मीडिया पर वायरल

गोरखपुर,संवाददाता। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वायरल वीडियो के साथ ही पीड़िता का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस अकाउंट पर 57 पोस्ट, 5 फॉलोअर और 86 फॉलोइंग किए गए थे। इसे अब पुलिस ने संदिग्ध साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। इधर, मामले में एक और महिला आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। वह महिला भी पहले जेल भेजी गई सिमरन के साथ स्पा सेंटर में काम करती थी। होटल में दुष्कर्म की शिकार किशोरी का बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें किशोरी का हाथ की नस काटते हुए दिख रहा है। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो घटना से पहले का है और इस पर गंभीरता से जांच की जा रही है।

मामले में पुलिस अब तक एक महिला समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वायरल वीडियो के साथ ही पीड़िता का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस अकाउंट पर 57 पोस्ट, 5 फॉलोअर और 86 फॉलोइंग किए गए थे। इसे अब पुलिस ने संदिग्ध साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। इधर, मामले में एक और महिला आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। वह महिला भी पहले जेल भेजी गई सिमरन के साथ स्पा सेंटर में काम करती थी। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर काम चल रहा है।

सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। किशोरी की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर न करें, ताकि मामले की जांच प्रभावित न हो।

सीओ का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में आएंगे और जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल और फिजिकल सबूतों के आधार पर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।

बेरोजगारों संग की ठगीः नौकरी दिलाने के नाम पर भेजा दुबई न कंपनी थी न नौकरी– ठग लिए 30.45 लाख रुपये, गिरफ्तार

गोरखपुर,संवाददाता। आरोप है कि फुरकान, उसकी पत्नी इमराना खातून, पिता फारूक अली व अन्य के बैंक खातों में अलग–अलग तिथियों पर 49 लोगों के करीब 24.30 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद 12 युवकों का वीजा कराकर उन्हें दुबई भेजा गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि न तो कोई कंपनी है और न ही कोई नौकरी। सभी युवक बेरोजगार हालत में फंस गए। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर नायब काजी से 30.45 लाख रुपये की ठगी के आरोपी इनामी जालसाज को राजघाट पुलिस ने संतकबीरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के ठाणे खंडु पाडा भिवंडी डांडेकरवाडी निवासी फारुक अली निजामी के रूप में हुई है।

आरोपी को वर्ष 2023 से पुलिस खोज रही थी। वह संतकबीरनगर जिले के दुधरा इलाके में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर स्थित रशीद मंजिल निवासी मोहम्मद अजहर से जुड़ा है, जो इस्लामिक मुफ्ती होने के साथ–साथ शहर के नायब काजी भी हैं। 20 अगस्त 2023 में उन्होंने राजघाट थाने में फुरकान अली निजामी, उसकी पत्नी इमराना खातून, फुरकान के पिता फारूक अली समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप था कि उनके परिचित फुरकान अली निजामी और उसके परिजनों ने दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे और उनके जानने वालों से लाखों रुपये ठग लिए। पीड़ित के अनुसार, फुरकान अली ने दुबई (यूएई) में 70 लोगों की नौकरी की वैकेंसी होने का दावा किया था। चॉकलेट कंपनी, ट्रॉली बैग और परफ्यूम पैकिंग जैसे पदों पर नियुक्ति का भरोसा दिलाया। इसके एवज में प्रत्येक व्यक्ति से वीजा से पहले 30 हजार और वीजा मिलने के बाद 40 हजार रुपये लेने की बात तय हुई। विश्वास दिलाने के लिए डिलाइट चॉकलेट फैक्टरी एलएलसी का एग्रीमेंट भी दिखाया गया, जो बाद में फर्जी निकला।

आरोप है कि फुरकान, उसकी पत्नी इमराना खातून, पिता फारूक अली व अन्य के बैंक खातों में अलग–अलग तिथियों पर 49 लोगों के करीब 24.30 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद 12 युवकों का वीजा कराकर उन्हें दुबई भेजा गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि न तो कोई कंपनी है और न ही कोई नौकरी। सभी युवक बेरोजगार हालत में फंस गए।

नायब काजी ने बताया कि मानवीय आधार पर उन्होंने अपने पास से करीब 6.15 लाख रुपये खर्च कर होटल, भोजन और हवाई टिकट की व्यवस्था कर 5 अगस्त 2023 को सभी युवकों को देश वापस बुलाया। रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी और बाद में जान से मारने की धमकी देने लगा।

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 15–15 हजार रुपये का इनामी घोषित किया था। पुलिस टीम ने बुधवार को फुरकान के पिता फारूक को संतकबीरनगर के दुधरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भागे हुए अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

पंकज गुप्ता, थानाप्रभारी राजघाट

'शराब की लत ने बढ़ाया टकराव, दूसरी पत्नी बनने के लिए भी हो गई थी राजी', प्रिया की सौतेली बहन का खुलासा

गोरखपुर,संवाददाता। मुंबई निवासी प्रिया शेट्टी हत्याकांड का पुलिस ने भले ही पर्दाफाश कर दिया है लेकिन हत्या के तौर–तरीकों और निर्वस्त्र शव मिलने पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि यह वारदात अचानक नहीं बल्कि सोची–समझी साजिश का अंजाम है। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में प्रिया हत्याकांड की जांच जैसे–जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे–वैसे उसके निजी जीवन से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं। मंगलवार को प्रिया की सौतेली बहन किरन जायसवाल अपने पड़ोसी के साथ शहर पहुंचीं और पुलिस से सीधे संपर्क कर घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि बेटे के हक की लड़ाई, और शराब की लत ने प्रिया और विजय में टकराव बढ़ाया। पीपीगंज थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि दोपहर बाद किरन और उनका पड़ोसी हवाई यात्रा के जरिये वाराणसी पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से पीपीगंज थाने आए। थाने में उन्होंने घटना के क्रम, हत्या के कारणों और अब तक की जांच प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद वे कस्बा चौकी इंचार्ज समेत चार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पुलिस को दिए गए बयान में किरन ने बताया कि प्रिया का विजय कुमार साहनी के साथ रहने का मुख्य कारण अपने बेटे का भविष्य और उसका अधिकार सुरक्षित करना था। प्रिया चाहती थी कि विजय उसके बेटे की जिम्मेदारी स्वीकार करे। यही नहीं प्रिया, विजय के साथ दूसरी पत्नी के रूप में रहने को भी राजी थी। प्रिया को उम्मीद थी कि इस समझौते से उसके बेटे को स्थायित्व मिलेगा। इसी सहमति के आधार पर वह विजय के साथ रह रही थी।

शराब की लत ने बिगाड़े हालात

किरन ने बताया कि विजय के संपर्क में आने के बाद प्रिया की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया और वह शराब की लत की शिकार हो गई। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ। वह अक्सर प्रिया के साथ रहता था। ये बात विजय करी पत्नी संध्या को नागवार गुजरती थी। दो बार पुलिस केस भी संध्या ने किया था, लेकिन प्रिया के पास शादी के लीगल दस्तावेज के आगे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। समझौते के बाद छोड़ दिया जाता था। किरन ने पुलिस को बताया कि बेटे के भविष्य को लेकर प्रिया और विजय के बीच अक्सर विवाद होता था। विजय की पहली पत्नी संध्या और बच्चों की मौजूदगी के कारण यह रिश्ता लगातार तनाव में रहता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन विवादों का असर दोनों के व्यवहार पर भी दिखने लगा था।

तौर–तरीके बता रहे अचानक नहीं सुनियोजित हुई प्रिया की हत्या

मुंबई निवासी प्रिया शेट्टी हत्याकांड का पुलिस ने भले ही पर्दाफाश कर दिया है लेकिन हत्या के तौर–तरीकों और निर्वस्त्र शव मिलने पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि यह वारदात अचानक नहीं बल्कि सोची–समझी साजिश का अंजाम है। उनका तर्क है कि आरोपियों की मंशा निर्वस्त्र शव के पीछे पहचान छिपानी ही थी तो उसे कहीं दूर खाली स्थान पर भी ठिकाने लगाते। उनका मानना है कि आरोपी विजय और उसकी पत्नी ने हत्या का यह तरीका जानबूझकर चुना ताकि साक्ष्यों के अभाव में उन्हें लाभ मिल सके। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे कहते हैं– कानूनी कार्रवाई साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इस हत्याकांड में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और न ही वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। एक स्कूटी पर तीन लोग गए और दो लोग आते दिखे। इससे यह साबित नहीं होता है कि हत्यारोपी कौन है। इसका लाभ केस ट्रायल में आरोपियों को मिल सकता है। पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो पुलिस ने परिस्थितिजन्य मिले साक्ष्यों के आधार पर पर्दाफाश किया है। अब पुलिस को एक–एक कड़ी को जोड़कर साक्ष्य जुटाने होंगे। कस्टडी में लिए गए बयान को कोर्ट में साक्ष्य नहीं माना जाएगा। पीके दुबे ने बताया कि हत्या का तरीका गला दबाकर और चेहरे को कूंच देना अपराधियों द्वारा पहचान छिपाने की कोशिश बताता है, जिससे प्रीमीडिटेशन यानी योजना बनाकर हत्या का संकेत मिलता है। कानूनी तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या उसने साक्ष्यों और कानून की धाराओं की समझ का लाभ उठाकर शव की पहचान छुपाई। अगर अदालत को यह लगे कि अपराध योजना बनाकर किया गया तो सजा और भी कठोर हो सकती है। वीडियो कॉल से अंतिम दर्शन, गवाही और शुरुआती जांच में हुई देरी अभियोजन पक्ष को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकती है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति के भय से छुपकर संबंध बनाता है या विवाह करता है तो वह लगातार मानसिक तनाव, अपराधबोध और असुरक्षा की स्थिति में रहता है। यह दोहरी जिंदगी व्यक्ति के भीतर तीव्र मानसिक संघर्ष पैदा करती है। मनोविज्ञान में इसे मोरल डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए पीड़ित को 'समस्या' या 'बोझ' के रूप में देखने लगता है।

पति–पत्नी की ओर से संयुक्त रूप से अपराध किया जाना साझा नैतिक औचित्य का उदाहरण है। इसमें एक–दूसरे का समर्थन अपराधबोध को कम कर देता है। यह अत्यंत खतरनाक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति का कारण केवल कानून की कमी नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक प्रतिष्ठा का अतिशय भय और रिश्तों में ईमानदारी की कमी है।– **प्रो. अनुभूति दुबे, मनोवैज्ञानिक, डीडीयू**

कोयंबटूर की तर्ज पर बरेली में बनेगा यूपी का पहला मीडिया टावर

बरेली,संवाददाता। बरेली को एक और सौगात मिलने जा रही है। बीडीए रामगंगानगर के सेक्टर–सात में मीडिया टावर को निर्माण कराएगा। बीडीए का दावा है कि यह प्रदेश का पहला मीडिया टावर होगा। बीडीए कोयंबटूर की तर्ज पर अब बरेली में 11 मीटर ऊंचे अत्याधुनिक मीडिया टावर का निर्माण कराएगा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) का दावा है कि यह प्रदेश का पहला मीडिया टावर होगा। यह न केवल सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बनेगा, बल्कि शहर की सुंदरता में भी चार चांद लगाएगा। पर्यटन में भी वृद्धि होगी। बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर–सात में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से इस टावर का निर्माण कराया जाएगा। इसमें सिंगापुर के प्रसिद्ध 'गार्डन बाय द वे' पार्क की तरह ढलान वाली एलईडी स्क्रीन का उपयोग किया जाएगा। मीडिया टावर न केवल देखने में भव्य होगा, बल्कि तकनीकी रूप से भी काफी सक्षम होगा। 11 मीटर ऊंचे टावर में आठ मीटर का डिस्प्ले एरिया होगा। टावर में लाखों रंगों वाली 5,000 एलईडी लगाई जाएंगी, जो झिलमिलाहट (फ्लिकर इफेक्ट) के साथ रात में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी।

स्क्रीन पर दिखेंगे विज्ञापन

इसकी स्क्रीन पर समाचार, सरकारी योजनाओं और विज्ञापनों का प्रसारण उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। टावर की ढलान वाली स्क्रीन पर विज्ञापन देना विज्ञापनदाताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय होगा।

इन्फोटेनमेंट हब के रूप में किया जाएगा विकसित

बीडीए को विज्ञापन से राजस्व मिलने की भी उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इस टावर को इन्फोटेनमेंट (सूचनात्मक मनोरंजन) हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा, जहां से मीडिया प्लेयर और कंटेंट को नियंत्रित किया जा सकेगा।

जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

बीडीए के मुख्य अभियंता एपीएन सिंह के मुताबिक, इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। यह टावर न केवल बरेली को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा, बल्कि राहगीरों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। आने वाले समय में यह मॉडल प्रदेश के अन्य बड़े शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।

चाइनीज मांझे पर सीएम का सख्त एक्शन, पूरे प्रदेश से किया बैन, लखनऊ में हुई थी दर्दनाक मौत

लखनऊ,संवाददाता। यूपी में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं, इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध सख्त निर्देश जारी किए हैं। राजधानी लखनऊ के बाजारखाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

बाजारखाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग के तार के हाईटेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो मेट्रो ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी जिसकी उच्चस्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

पिता पर दो करोड़ का कर्ज

फोन बेचकर किया था बिजली का रीचार्ज, गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में एक और नया खुलासा

गाजियाबाद,संवाददाता। तीन बहनों के खुदकुशी मामले में एक और खुलासा हुआ है। सुसाइड लड़कियों के पिता चेतन कुमार पर दो करोड़ रुपये का कर्ज है। चेतन कुमार एक स्टॉक ट्रेडर हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नौवीं मंजिल के अपार्टमेंट से तीन बहनों की खुदकुशी के मामले ने जांचकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है। जैसे–जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए–नए खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में तीनों लड़कियों के पिता ने बताया कि बच्चे एक कोरियन गेम खेल रहे थे जिसमें उन्हें कुछ काम करने होते थे, और आखिरी काम आत्महत्या करना था।

उधर, पुलिस ने बताया कि तीनों बहनें मोबाइल फोन पर कोरियन शो देखती थीं। पुलिस ने यह भी कहा कि परिवार में दूसरी समस्याएं भी थीं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या कर्ज थी। पुलिस ने बताया कि लड़कियों के पिता चेतन कुमार पर दो करोड़ रुपये का कर्ज है। चेतन कुमार एक स्टॉक ट्रेडर हैं, वो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं। चेतन कुमार को शेयर बाजार में पैसा निवेश करने के दौरान तीन वर्ष पूर्व दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

चेतन ने मोबाइल बेचकर 10 दिन पूर्व ही बिजली का रीचार्ज किया

माहभर की मेहनत के बाद वह मात्र इस रकम का ब्याज ही दे पा रहे हैं। सोसायटी के पदाधिकारियों के मुताबिक, आर्थिक तंगी के चलते चेतन ने घर में रखा एक मोबाइल बेचकर 10 दिन पूर्व ही बिजली का रीचार्ज किया है।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था चेतन

कोरोना काल में शेयर बाजार में आई उथल–पुथल के बीच चेतन को दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके चलते वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार के आर्थिक परेशानियों में फंसे होने के चलते उसके करीबी रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली थी। भारत सिटी सोसायटी के फ्लैट में तीन किशोरियों की सामूहिक आत्महत्या के बाद पुलिस को मिला नोट।

आर्थिक तंगी के चलते तीनों बेटियों ने स्कूल छोड़ा

शेयर मार्केट में हुए घाटे की भरपाई के लिए वह दिन–रात मेहनत करके भी कुछ रुपये ही जमा कर पा रहा था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसी के चलते तीनों बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया था। तंगी के चलते घर में कई बार क्लेश भी हो चुका था।

100 साल की उम्र में बाइज्जत बरी

42 साल पुराने कत्ल के मामले में कोर्ट का फैसला

प्रयागराज,संवाददाता। हमीरपुर में हुई हत्या के एक मामले में 100 साल का बुजुर्ग बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन की अंतिम बेला में सजा देना न्याय को निरर्थक बना देता है। हमीरपुर निवासी शख्स ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो तो दशकों की देरी के बाद उसे सजा देना न्याय को एक निरर्थक अनुष्ठान में बदलने जैसा है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने 42 साल पुराने हत्या के मामले में 100 साल की आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग को बरी कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि न्याय मानवीय परिस्थितियों से अलग कोई अमूर्त वस्तु नहीं है। कानून इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकता कि बढ़ती उम्र अपने साथ शारीरिक कमजोरी और निर्भरता लाती है। सजा का उद्देश्य सुधार और समाज का हित होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लंबित मुकदमे में बिता चुका हो तो सजा का व्यावहारिक और नैतिक बल समाप्त हो जाता है।

कोर्ट ने यह भी माना कि दशकों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह खुद में एक कठोर सजा बन जाती है। 40 वर्षों तक अनिश्चितता और सामाजिक कलंक का सामना करना अपने आप में एक दंड है। यह मामला अगस्त 1982 का है। हमीरपुर निवासी धनी राम उर्फ धनइयां और सत्तीदीन को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कि थी और वे पिछले 40 वर्षों से जमानत पर थे। अपील के लंबित रहने के दौरान सत्तीदीन की मौत हो गई। वहीं, जीवित बचे धनीराम की उम्र वर्तमान में 100 वर्ष हो चुकी है। अदालत ने पाया कि न केवल अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा, बल्कि अभियुक्त की अत्यधिक उम्र और 42 साल का लंबा विलंब उसे पूरी तरह से दोषमुक्त करने के लिए अतिरिक्त आधार प्रदान करता है।

अब फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में पीएचडी का मौका

लखनऊ,संवाददाता। भाषा विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। भाषा विश्वविद्यालय में अब फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में अब फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। ललित कला संकाय के तहत बीए संगीत (वोकल) पाठ्यक्रम भी शुरू होगा। विवि में बुधवार को कुलपति प्रो. अजय तनेजा की अध्यक्षता में 25वीं अकादमिक परिषद की बैठक में ऐसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सभी विभागों के लिए 30 घंटे का एआई फॉर एवरीवन प्रमाणपत्र कोर्स शुरू होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में होगा। फार्मेसी संकाय के बीफार्मा चौथे वर्ष के पाठ्यक्रम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार दंपती समेत तीन की मौत

लखीमपुर खीरी ,संवाददाता। लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जलालपुर मोड़ के पास गोला से लखीमपुर की ओर जा रही कार को किसी वाहन ने टक्कर मारी दी। जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक है। हादसा बृहस्पतिवार तड़के करीब छह बजे हुआ। राहगीर शुभम रस्तोगी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएचसी गोला भेजा गया। जहां से एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। कार सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। दिल्ली से धर्म कुंडा बहराइच अपने घर जा रहे थे।

हादसे में घायल प्रवेश सिंह (25 वर्ष) पुत्र अजय पाल ने बताया कि वे सभी लोग दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहते थे। डेकोरेशन का काम करते थे। प्रवेश सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुकेश सिंह (25 वर्ष) पुत्र रमेश सिंह का तिलक था।

कार से सभी लोग बहराइच के लिए जा रहे थे। कार में मुकेश सिंह, सुनील सिंह पुत्र बिंद्रा सिंह (30 वर्ष), सुनील सिंह की दो वर्षीय पुत्री मानवी, सुनील की पत्नी सुधा सिंह (27 वर्ष) सवार थे। कार संतोष सिंह पुत्र रमेश सिंह (30 वर्ष) चल रहा था।

यूपी में एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय एक माह बढ़ा

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदन अभी लंबित होने के कारण विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावा व आपत्तियों का समय एक माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचन आयोग को इसका प्रस्ताव भेजकर मंजूरी भी प्राप्त कर ली है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि शुक्रवार यानी छह फरवरी तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों पर सुनवाई का अंतिम दिन था। अब एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके बाद 6 मार्च तक मतदाता दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। नवदीप रिणवा ने बताया कि सुनवाई की भी तिथि एक माह बढ़ाते

हुए 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च कर दी गई है। अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी।

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।

यह दूसरी बार है जब आयोग ने अंतिम सूची की समय–सीमा को आगे बढ़ाया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं को पूरी पारदर्शिता और न्याय देने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

3.26 करोड़ लोगों को नोटिस

आयोग अब उन मतदाताओं की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनके डेटा मैच नहीं हुआ है। लगभग तीन करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी है।

ये वे लोग हैं जिनका डेटा या तो मैच नहीं हुआ है या फिर वे अपने पते पर नहीं मिले हैं। नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे जिसके बाद ही उनके नाम सूची में शामिल करने या बरकरार रखने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं या कोई गलती सुधारना चाहते हैं तो अब आपके पास 6 मार्च तक का समय है। आप ऑनलाइन माध्यम या अपने क्षेत्र के बीएलओ के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई थी। पहले के कार्यक्रम के अनुसार छह जनवरी को ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि छह फरवरी निर्धारित की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में आ रहे आवेदनों और डेटा मिलान की प्रक्रिया को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे एक महीना और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार नाम जुड़वाने के लिए (फॉर्म 6) कुल 37,80,414 आवेदन आए हैं। नाम कटवाने के लिए (फॉर्म 7) कुल 82,684 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। वहीं ओवरसीज मतदाता यानी विदेश में रहने वाले 1073 मतदाताओं ने भी आवेदन किया है।

बाराबंकी में एसपी ने पुलिसकर्मियों की तैनाती में किया फेरबदल

संवाद सूत्र, बाराबंकी। पुलिसिंग को चुस्त–दुरुस्त और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई के साथ फेरबदल किए। तीन चौकी प्रभारियों से जिम्मेदारी हटा ली गई, जबकि एक चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया।

18 उपनिरीक्षकों को विभिन्न थानों व चौकियों में नई तैनाती दी गई है। देवा के चौकी मित्तई के प्रभारी अश्वनी कुमार सिंह को लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक रामकृपाल सिंह को सम्मन सेल प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी को अपराध शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जहांगीराबाद से निरीक्षक रामकृपाल चौहान को रामसनेहीघाट में अतिरिक्त निरीक्षक, एसएसआइ बदोसराय जय प्रकाश यादव को उसी थाने में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है।

पुलिस लाइन में तैनात 18 उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। अनुराग पाठक को चौकी प्रभारी सिविल लाइन, संतोष कुमार मौर्य को चौकी प्रभारी अहमदपुर, जगन्नाथमणि त्रिपाठी को चौकी प्रभारी मित्तई, उपेंद्र सिंह भदौरिया को चौकी प्रभारी लालपुर करौता बनाया गया है।

ब्राह्मणों के अपमान वाली फिल्म पर लगे प्रतिबंध, मायावती ने घूसखोर पंडित पर रोक लगाने की मांग की

लखनऊ,संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मणों के अपमान पर चिंता जताते हुए 'घूसखोर पंडित' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि यह दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब फिल्मों में भी 'पंडित' को घूसखोर बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। बसपा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जातिसूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।

निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इसके पहले, हजरतगंज कोतवाली में फिल्म घूसखोर पंडित के निर्देशक व उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निर्देशक के खिलाफ जातिगत भावनाएं आहत करने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक व जातिगत भावनाओं को आहत करने के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। फिल्म का शीर्षक एक विशेष जाति (ब्राह्मण) को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया है जिसे लेकर समाज में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर व उनकी टीम द्वारा समाज में वैमनस्यता फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने और सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से इस सामग्री को प्रकाशित किया गया है। किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी

अफसरों में मची खलबली, मेरठ 9 तो गाजियाबाद 11 फरवरी...

मुख्यमंत्री तक पहुंची तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें। मुख्य सचिव ने फरवरी में निरीक्षण के दिए आदेश। मेरठ मंडल में 9 फरवरी से शुरू होंगे कलेक्ट्रेट निरीक्षण।

संवाददाता, मेरठ। तहसीलों में मनमानी और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। भाकियू संगठन बार बार विभिन्न तहसीलों पर इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। यह शिकायतें अब मुख्यमंत्री तक जा पहुंची है। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी तहसील और सभी कलक्ट्रेट का समय समय पर निरीक्षण करने का आदेश कमिश्नर और डीएम को दिया है। ताकि यह मनमानी रोकी जा सके। यह निरीक्षण फरवरी महीने में ही पूरे करके उसकी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। जिसे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के सभी जनपदों के डीएम कार्यालय के निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले 9 फरवरी को मेरठ जनपद का निरीक्षण होगा। जिसकी तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सभी कलक्ट्रेट और तहसीलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि निरीक्षण से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने फरवरी महीने में विशेष अभियान चलाकर सभी तहसीलों और कलक्ट्रेट का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। निरीक्षण के लिए विशेष बिंदु भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट को संकलित करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

कमिश्नर ने जारी किया कार्यक्रम, डीएम जल्द करेंगे

मुख्य सचिव का आदेश मिलते ही मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालयों (कलक्ट्रेट) का निरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले 9 फरवरी को मेरठ में निरीक्षण होगा। 11 को गाजियाबाद, 12 को बुलंदशहर, 14 को बागपत, 20 फरवरी को हापुड़ तथा 26 फरवरी को गौतमबुद्धनगर में कलक्ट्रेट का निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है कि डीएम भी जल्द तहसीलों के निरीक्षण का कार्यक्रम जारी करेंगे। वहीं कमिश्नर के निरीक्षण के लिए कलक्ट्रेट कर्मियों ने गुरुवार से ही तैयारी शुरू कर दी। एडीएम सिटी मे भी विभिन्न पटलों पर पहुंचकर तैयारी कराई।

इन बिंदुओं पर होगा निरीक्षण

तहसील परिसर में साफ सफाई और जनसुनिधाएं, राजस्व न्यायालयों में मामलों के निस्तारण की गति, अन्य प्रशासनिक कार्यों को शिकायतों के निस्तारण में लगने वाली अवधि का आकलन होगा। जबकि कलक्ट्रेट में जनसुविधाओं के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में सुनवाई, राजस्व अभिलेखागार के अभिलेखों का रखरखाव और नकल आवेदनों का निस्तारण, चरित्र हैसियत, जाति समेत अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करना, चरित्र सत्यापन का कार्य तहसील दिवस और आइजीआरएस के मामलों के निस्तारण की स्थिति, शस्त्र लिपिक पटल की कार्यप्रणाली।

प्रिंस बन हिंदू लड़की से की अजफरूल ने दोस्ती...पहले किया दुष्कर्म, फिर गैंगरेप– कई लड़कियों को बनाया शिकार

बस्ती,संवाददाता। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्लिम अजफरूल ने धर्म बदल कर खुद को प्रिंस बताकर पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म और गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि ऐसे ही कई लड़कियों को अजफरूल ने धर्म बदल कर दुष्कर्म का शिकार बनाया था।

हालांकि अभी शिकायतकर्ता सामने नहीं आए हैं। कोतवाली में दर्ज गैंगरेप के मुकदमे में नामजद मुख्यारोपी अजफरूल ऊर्फ प्रिन्स को बस्ती पुलिस ने महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को महाराष्ट्र के न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर बस्ती लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि आरोपी प्रिंस को पकड़ लिया गया है।उसे नियमानुसार बस्ती लाया जा रहा है।

कलवारी थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने तहरीर देकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि वह पुरानी बस्ती के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। आरोप है कि जनवरी 2022 में पुरानी बस्ती क्षेत्र के रहने वाले प्रिंस नाम के एक युवक से उनकी अस्पताल में मुलाकात हुई।

आरोप है कि उसने खुद को हिन्दू बताया। फोन पर दोनों की बात होने लगी। एक दिन उसने फोन कर कहा कि तुमको यहां पर कम वेतन मिलता है। मैं तुम्हे दूसरे हॉस्पिटल में लगवा दूंगा। दिसम्बर 2022 में दूसरे हॉस्पिटल के मालिक से मिलवाने के लिए कहकर वह दक्षिण दरवाजा स्थित एक लॉज में ले गया। यहां सिर पर कट्टा सटाकर जान से मार डालने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। बाद में घर ले जाकर गैंगरेप समेत अन्य आरोप लगाए थे। प्रकरण में एसपी अभिनंदन के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पुरानी बस्ती निवासी प्रिंस समेत अन्य लोगों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि मुस्लिम अजफरूल ने धर्म बदल कर खुद को प्रिंस बताकर पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म और गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि ऐसे ही कई लड़कियों को अजफरूल ने धर्म बदल कर दुष्कर्म का शिकार बनाया था। हालांकि अभी शिकायतकर्ता सामने नहीं आए हैं।

यूपी पंचायत चुनाव 2026: वार्डवार परिसीमन के बाद पदों की संख्या में गड़बड़ी, आयोग ने दिए सुधार के निर्देश

लखनऊ,संवाददाता। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें वार्डवार परिसीमन के बाद पदों की संख्या में गड़बड़ी मिली है। निर्वाचन आयोग ने सुधार के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत वार्डवार परिसीमन के बाद ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या दर्ज करने में कई जिलों से त्रुटियां सामने आई हैं। आयोग पोर्टल पर फीड किए गए आंकड़ों में पंचायती राज विभाग की आधिकारिक सूची से अंतर पाया गया है। इसे गंभीर मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को सुधार के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विभागीय सूची से मिलान के बाद ही संख्या पोर्टल पर दर्ज की जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2026 तक प्रस्तावित हैं और अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी होगी।

मेरठ में 14 करोड़ का स्टांप घोटाला

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को दिया सुनवाई का निर्देश

संवाददाता, मेरठ। जनपद में बैनामों में फर्जी और पुराने स्टांप पेपर लगाकर वर्ष 2015 से 2023 के बीच लगभग 14 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला दस्तावेज लेखक के रूप में कार्यरत एक अधिवक्ता द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में जेल में है। इस घोटाले के तहत संपत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों से वसूली की जा रही है। हालांकि फर्जी स्टांप का उपयोग पूर्व में भी किया गया था, लेकिन कार्रवाई की समय सीमा समाप्त होने के कारण उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वसूली के नोटिसों के विरुद्ध 15 पीड़ितों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को ही तीन महीने में सुनवाई करके निर्णय लेने का आदेश दिया है। वर्ष 2020 से 2023 के बीच 999 बैनामों में 7.50 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। इनमें से अधिकांश लोगों से वसूली की जा चुकी है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति के आदेश पर वर्ष 2015 से 2020 के बीच के बैनामों के स्टांप पेपर का सत्यापन किया गया, जिसमें 932 बैनामों में 6.39 करोड़ रुपये के फर्जी स्टांप पाए गए।

वर्तमान में इन बैनामों के खरीदारों को नोटिस भेजकर वसूली का कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों ने फर्जी स्टांप की राशि जमा नहीं की है, उनके खिलाफ सहायक महानिरीक्षक निबंधन, एडीएम वित्त और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई चल रही है। वसूली के नोटिस प्राप्त करने वाले 15 पीड़ितों ने हाई कोर्ट में अलग–अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें उन्होंने वसूली नोटिसों को निरस्त करने की मांग की थी।

इन याचिकाओं पर जस्टिस विवेक सरन की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी और संबंधित निबंधन अधिकारियों के न्यायालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

साथ ही संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इन मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। सभी याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दिए हैं।

तीन साल पहले खुला था स्टांप घोटाला

यह स्टांप घोटाला वर्ष 2023 में उजागर हुआ था। जांच में वर्ष 2020 से 2023 के बीच हुए बैनामों का सत्यापन किया गया। विधानसभा की प्राक्कलन समिति के आदेश पर 2015 से 2020 के बीच के बैनामों में लगे भौतिक स्टांप पेपर का भी सत्यापन किया गया।

हैकर्स के निशाने पर रिंकू सिंह

फेसबुक आईडी हैक, अचानक बिगड़ी पिता खान चंद की तबीयत, इलाज के लिए नोएडा रेफर

अलीगढ़,संवाददाता। साइबर हैकरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी हैक कर ली है। साथ में 1.6 मिलियन फॉलोअर वाली मोनेटाइज आईडी से मिलने वाली रकम को भी हैकर हड़प रहे हैं। मैदान पर छक्कों की बारिश करने वाले टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह इन दिनों एक अलग ही 'पिच' पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अलीगढ़ के इस चहेते खिलाड़ी की फेसबुक आईडी को कुछ असामाजिक तत्वों ने हैक कर लिया है। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे शहर में सनसनी मच गई। हैकर्स ने आईडी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे प्रशंसक और परिवार दोनों गहरे तनाव में हैं।

मैदान के बाहर 'गुगली' का शिकार

रिंकू सिंह की सोशल मीडिया पहचान पर हुए इस हमले के बाद उनके भाई ने तुरंत एक्शन लिया।

रिंकू के भाई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन 'डिजिटल हमलावरों' की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने इस स्टार खिलाड़ी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने की कोशिश की है।

सुरक्षा के कड़े पहरे में परिवार

इस घटना के बाद रिंकू सिंह के ओजोन सिटी स्थित आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक–चौबंद कर दी गई है। चप्पे–चप्पे पर पुलिस तैनात है। जहां एक ओर पुलिस हैकर्स का सुराग लगा रही है, वहीं दूसरी ओर रिंकू के घर में चिंता का माहौल है।

पिता की बिगड़ी तबीयत

इस पूरे घटनाक्रम और मानसिक तनाव के बीच रिंकू सिंह के पिता, खान चंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें नोएडा के एक अस्पताल लेकर रवाना हुए हैं। पुलिस का कहना है मामले की जांच साइबर सेल की मदद से की जा रही है। जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और आईडी को रिकवर करने की कोशिश जारी है।

लापरवाही के गड्ढे में गई एक और जान

परिजनों का आरोप- पुलिस ने आखिरी लोकेशन बताई, लेकिन ढूंढने में मदद नहीं की

दिल्ली ,एजेंसी। जल बोर्ड के एक खुले गड्ढे में गिरकर एक निजी बैंक में कार्यरत युवक कमल की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण कमल की जान बचाई नहीं जा सकी।

दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले कमल चंदानी (25 वर्ष) के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई ने कहा, उसका भाई एचडीएफसी बैंक की रोहिणी ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर था। हादसे के बाद पर्दे लगाए गए, पहले केवल पीछे वाला पर्दा लगा हुआ था। भाई ने आगे कहा, जब मैंने आखिरी बार कमल से बात की थी तो बोला था कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा। जब उसने उसे रात 12:30 बजे दोबारा फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया। युवक ने कहा कि, इसके बाद हम परेशान हो गए, फिर हमने उसकी तलाश शुरू की। मैं पहले रोहिणी स्थित उसके कार्यालय गया, फिर जनकपुरी पुलिस स्टेशन गया।

'गुरुवार रात 12.30 बजे बंद हो गया फोन, सुबह शव मिलने की सूचना आई'

मृतक के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने हमको इस इलाके में उसकी आखिरी लोकेशन बताई, लेकिन उसे ढूंढने में मदद नहीं की। हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। यह घोर लापरवाही है। मेरा भाई पागल नहीं था कि वह जानबूझकर गड्ढे में गाड़ी गिरा दे। रात 1:30 बजे मैंने गड्ढे में जाकर देखा, लेकिन वह उस समय वहां नहीं था। हमने कम से कम छह पुलिस स्टेशनों का पर गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुबह जब मैंने दोबारा अपने भाई के फोन नंबर पर कॉल किया, तो पुलिस ने फोन उठाया और हमें बताया कि उसका शव गड्ढे से बरामद कर लिया गया है। अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती, तो मेरा भाई आज जीवित होता।

यह है मामला

कमल गुरुवार की रात करीब 10 बजे ऑफिस से घर लौट रहा था। गड्ढे में गिरने के कारण जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार पूरी रात थानों के चक्कर लगाता रहा। परिवार ने जल बोर्ड की लापरवाही की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने नोएडा में इंजीनियर युवराज के साथ हुई घटना की दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। रात का समय था, कमल बाइक से घर लौट रहा था। परिजनों का आरोप है कि गड्ढे को घेरने के लिए केवल एक पर्दा लगा था। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में वह सीधे गड्ढे में गिर गया। गहरे गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई।

जलशक्ति मंत्री को बंधक बनाने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ नोटिस जारी

लखनऊ,संवाददाता। यूपी के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और सात दिन में जवाब मांगा गया है। बीती 30 जनवरी को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जहां से लौटने पर चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह ने उन्हें रोककर बंधक बना लिया। इससे पार्टी नेतृत्व के सामने असहज करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। अब पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनसे मामले पर सात दिन में जवाब मांगा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोकने के बाद भाजपा विधायक का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कहते हुए सुने जा सकते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। बंधक बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जनता और विकास से जुड़ा मुद्दा है।

'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद

दिल्ली,एजेंसी । मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर 'घूसखोर पंडत' विवादों में घिर गई है. इस शो की घोषणा बुधवार को मुंबई में एक इवेंट में की गई और इसका टीज़र भी लॉन्च किया गया. फिल्म में मनोज बाजपेयी अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट और अनैतिक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है. इस फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है और इसे शाह और नीरज पांडे ने मिलकर लिखा है. इसमें नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी अहम किरदारों में हैं. हालांकि ये फिल्म विवादों में फंस गई है और इस फिल्म की टीम के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई है. चलिए यहां पूरा मामला जानते हैं.

घूसखोर पंडित को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ?

'नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स' इवेंट के दौरान 'घूसखोर पंडत' का टीजर रिलीज किए जाने के के तुरंत बाद ही ये विवादों में फंस गई. मुंबई के एक वकील, आशुतोष दुबे ने टाइटल पर आपत्ति जताते हुए नेटफ्लिक्स और फिल्म बनाने वालों को लीगल नोटिस भेजा. पंडत (पुजारी, धार्मिक विद्वान) शब्द का इस्तेमाल घूसखोर (उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जो रिश्वत लेते हैं) के साथ किया गया है.

नोटिस में दावा किया गया है कि यह मेल अपमानजनक है और 'पंडित समुदाय' की गरिमा पर हमला है।

अहान के कारण बंद हुई 'सनकी'

सुनील शेट्टी ने बेटे पर लगे आरोपों को बताया गलत; बोले- ये उसके साथ नाइंसाफी है

एंटरटेनमेंट डेस्क। अहान शेट्टी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बीच अब अहान शेट्टी की फिल्म 'सनकी' के बंद होने की चर्चाएं एक बार फिर से उठी हैं। दरअसल, इस फिल्म के बंद होने की वजह अहान शेट्टी के सपोर्टिंग स्टाफ पर आने वाले अधिक खर्च को बताया गया था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि अहान शेट्टी के सहयोगी स्टाफ पर अधिक खर्च आने के कारण मेकर्स ने 'सनकी' फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इन चर्चाओं पर अहान के पिता व अभिनेता सुनील शेट्टी ने प्रतिक्रिया दी है।

प्रोड्यूसर ने फैलाईं अफवाहें

2021 में अहान की डेब्यू फिल्म 'तड़प' के रिलीज होने के बाद उनकी अगली फिल्म 'सनकी' को अचानक रोक दिया गया। बॉलीवुड हंगामा की 2024 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह फैसला अहान के साथ आए लोगों के कारण कथित तौर पर हुए खर्चों से बढ़ी चिंताओं के बाद लिया गया है। अब लहरें रेट्रो के साथ बातचीत में अभिनेता सुनील शेट्टी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने बेटे अहान के प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि अहान ने कभी भी अपने साथ आए लोगों को हद से ज्यादा नहीं रखा। ये सब अफवाहें हैं। ये अफवाहें निर्माता की सुविधा के लिए फैलाई गई हैं। अगर निर्माता कहता है कि वह बिल दिखा सकता है, तो मैं देखूंगा। ऐसे में पिता को दखल देना पड़ता है और मैं साफ तौर पर दखल दूंगा। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ मत फैलाओ, क्योंकि यह अहान के साथ नाइंसाफी है।

अहान खुद उठाते हैं अपने स्टाफ का खर्च

सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि अहान अपने साथ आने वाले लोगों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। अगर वे उनके साथ आते हैं, तो उनका खर्च वही उठाते हैं। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है। जब सुनील शेट्टी घर से खाना–पानी लाते हैं, तो मेरे स्टाफ को कहा गया है कि अगर आप यूनिट का खाना खा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से खाना मंगवाना चाहते हैं, तो बिल मेरे नाम से बनवाएं, निर्माता के नाम से नहीं। मेरा स्टाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए अहान का स्टाफ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अहान तो अभी–अभी इंडस्ट्री में आए हैं। यह उनका इंडस्ट्री में जमने का समय है, इसलिए कोई नखरे नहीं चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता।

कई रिपोर्ट्स में इन कारणों का भी किया गया जिक्र

कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साजिद नाडियाडवाला ने शुरू में 'सनकी' को आगे बढ़ाया था और प्राइम वीडियो के साथ एक बड़ा डिजिटल सौदा भी किया था।

हालांकि, इस सबके बावजूद सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से कम कमाई के कारण प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसके साथ ही कथित तौर पर अहान के सपोर्ट स्टाफ का अत्यधिक खर्च भी इसका कारण बना। लेकिन अब सुनील शेट्टी ने अहान के सपोर्ट स्टाफ के खर्च की बात को झूठा करार दिया है।

चार साल बाद 'बॉर्डर 2' में नजर आए अहान

अहान शेट्टी ने साल 2021 में आई एक्शन–रोमांटिक फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। हालांकि, इसके बाद लगभग चार साल से अधिक समय तक वो बड़े पर्दे से दूर रहे। अब इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' अहान की दूसरी फिल्म है। फिल्म में उन्होंने नेवी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वहीं अहान के काम को भी पसंद किया गया है।

कौन हैं जिया शंकर

बिग बॉस ओटीटी फेम जिया शंकर का नाम एल्विश यादव के साथ जुड़ रहा है, एल्विश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी वजह से हंगामा मच गया है और जिया चर्चा में छा गई हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में छा गई हैं. दरअसल, हाल ही में एल्विश ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जिया को टैग किया था. उसके बाद से फैंस जिया के बारे में छोटे–बड़ी हर बात जानने के लिए उत्सुक हैं.

जिया शंकर का जन्म 17 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्म एंथा अंदंगा उन्नावे से की और उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख किया. जिया शंकर ने टीवी शो मेरी हानिकारक बीवी में उनकी डॉ इरावती देसाई और काटेलाल एंड संस में सुशीला रूहेल सोलंकी का किरदार निभाया है. जिया शंकर रियल लाइफ में बेहद काफी बिंदास हैं. इतना ही नहीं वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

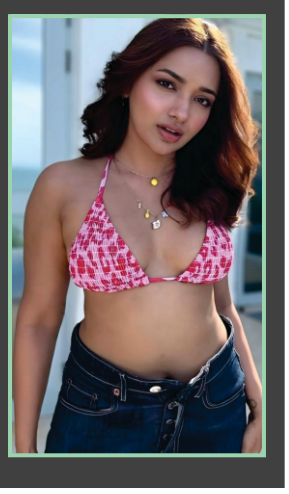

छोटी उम्र में बनी 3 बहुओं की सास

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर घर–घर में पॉपुलर होने वाली कनिका मान अब नागिन 7 में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.। 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' सीरियल में तीन–तीन बहुओं की सास का किरदार निभा चुकी गुड्डन उर्फ कनिका मान अपने किरदार और एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी है. इतना ही नहीं उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की सास बनने का भी टैग मिल चुका है. और अब वे एकता कपूर की सुपरहिट सीरियल नागिन 7 में नजर आने वाली हैं जी टीवी का वो पॉपुलर सीरियल 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' जिसने अपनी कहानी से सास–बहु के रिश्ते के मायने ही बदल दिए. इस कहानी में तीन बहुएं मिलकर अपने 40 साल के ससुर अक्षत जिंदल की शादी कराना चाहती हैं और उनके लिए एक बीस साल की गुड्डन को सास के रुप में चुनती हैं.इस सीरियल में सास यानी गुड्डन के किरदार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कनिका मान असल जिंदगी में उससे भी कई ज्यादा ग्लैमरस हैं.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अक्सर काफी एक्टिव रहती है, और एक से बढ़कर एक पोस्ट डालती रहती है.कनिका का जन्म 7 अक्टूबर 1993 को पानीपत, हरियाणा में हुआ. उन्होंने पंजाब युनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है. कनिका एक्टिंग में जाने से पहले मॉडलिंग किया करती थीं और इसके अलावा वे 2015 में मिस इंडिया एलीट में मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब भी जीत चुकी है.

एंटरटेनमेंट डेस्क। कपिल शर्मा की सीक्वल फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस कॉमेडी ड्रामा को अब घर बैठे एंजॉय किया जा सकता है.

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' अपने थिएट्रिकल री–रिलीज़ के लिए सुर्खियों में थी. वहीं जो लोग लंबे समय से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे, वे अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं. जी हां 'किस किसको प्यार करूं 2' ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है।.इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में हैं और उनके साथ चार लीड फीमेल एक्ट्रेस और एक स्पेशल अपीयरेंस भी है. चलिए जानते हैं ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है.

'किस किसको प्यार करूं 2' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

फाइनली किस किसको प्यार करूं 2 अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. कपिल शर्मा की लीड रोल वाली यह फिल्म शुक्रवार यानी आज जियो हॉटस्टार पर पर रिलीज़ हो गई है. इसे **OTTplay Premium** के सब्सक्रिप्शन के साथ देखा जा सकता है. अब्बास–मस्तान (ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर) द्वारा प्रोड्यूस की गई है।

हर्षित राणा की जगह टीम इंडिया में शामिल हो सकता है यह घातक गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क। तेज गेंदबाज हर्षित राणा की चोट ने भले ही भारतीय टीम प्रबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि राणा की जगह एक ऐसे गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है जो अन्य टीमों के लिए मुसीबत साबित होगा।

टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग सकता है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। हालांकि, उनकी जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल करने की तैयारी कर रहा है जो बाकियों के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीम प्रबंधन हर्षित की जगह मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में शामिल करने की तैयारी कर रहा है।

वॉर्म–अप मैच में चोटिल हुए थे राणा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वॉर्म–अप मुकाबले में हर्षित को घुटने में चोट लगी थी। अब उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्री–मैच कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उन्हें अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया गया है। फिजियो उनकी जांच कर रहे हैं। लेकिन हालत ठीक नहीं लग रही है। आज तक पता चल जाएगा।'

इस दौरान सूर्यकुमार ने बताया कि अगर हर्षित बाहर होते हैं तो टीम प्रबंधन की स्ट्रैटजी क्या होगी। उन्होंने कहा, 'हम देखेंगे कि पिछले 1–2 वर्षों में किन तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है या ऐसे गेंदबाज जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर 9 से बड़े शॉट लगाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो टॉप आठ क्या कर रहे हैं। हम सबसे अच्छे खिलाड़ी को चुनने की कोशिश करेंगे।'

पहले भी मिला था सिराज को मौका

अब खबर आई है कि मोहम्मद सिराज को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। वह पहले भी विश्व कप 2024 के लिए चुने गए स्क्वॉड में शामिल थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था। हालांकि, अब उम्मीद जताई जा रही है कि वह बुमराह के साथ भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा हो सकते हैं। सिराज ने पिछला टी20 30 जुलाई, 2024 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इसके बाद से वह टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।

सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल!

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच से हटने पर पाकिस्तान फोर्स मेज्योर का सहारा लेकर आईसीसी की सजा से बचना चाहता है। लेकिन न्यूट्रल वेन्यू, चयनात्मक बहिष्कार और सरकार–बोर्ड की नजदीकी उसकी दलील को कमजोर बनाती है। आईसीसी के पास आर्थिक और प्रशासनिक सख्त कदम उठाने का पूरा अधिकार है। फैसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया की दिशा तय करेगा। भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले का बहिष्कार करने की स्थिति में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज लागू करने की कोशिश कर सकता है। यह दावा द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में किया गया है।

अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है, तो भारत को सीधे दो अंक मिल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज उन अप्रत्याशित परिस्थितियों पर लागू होता है, जिनके चलते कोई पक्ष अपनी संविदात्मक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी अपने फैसले को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान सरकार के उस सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे सकता है, जिसमें भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की बात कही गई थी। पीसीबी यह तर्क दे सकता है कि उसे सरकार के निर्देशों के तहत यह फैसला लेना पड़ा और यह एक असाधारण स्थिति है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह उनका आखिरी विकल्प है, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच न खेलने की कोई और ठोस वजह उनके पास नहीं है।

बीसीसीआई ने बताया पीसीबी का तर्क कमजोर

इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दलील कमजोर है और ज्यादा टिकने वाली नहीं है। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'जब पाकिस्तान को उसी दिन अंडर–19 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी, जिस दिन उसकी सरकार ने टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार की बात कही थी, तो यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार में कोई खास फर्क नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीसीबी के संरक्षक हैं और बोर्ड का प्रमुख खुद मंत्री है।'

'क्रिकेट में राजनीति घुसा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश'

बीसीसीआई सूत्र ने आगे आरोप लगाया, 'पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड क्रिकेट में राजनीति मिला रहे हैं। भारतीय सरकार ने बार–बार सुरक्षा की गारंटी दी, फिर भी बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई। अब पाकिस्तान भी गैर–तार्किक रवैया अपना रहा है। आईसीसी आयोजनों में यह सहमति बनी हुई है कि भारत और पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इसके बावजूद मैच का बहिष्कार करना सिर्फ शरारत है।'

पाकिस्तान पीएम ने दोहराया बहिष्कार का फैसला

इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले के बहिष्कार के फैसले को दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर लिया है। इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, 'हमने टी20 विश्व कप को लेकर साफ स्टैंड ले लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे।' लेकिन इसी बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (च्ब्ठ) इस फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (प्ब्) की सख्त कार्रवाई से बच सकता है? इस एलान ने पूरे टूर्नामेंट को कानूनी और प्रशासनिक संकट में डाल दिया है।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

UPHIN/2023/90814

बृजेन्द्र कुमार

मो0. नं0. 7307180148,9170772370

Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः- समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

सबसे तेज शतक से सर्वाधिक छक्कों तक

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर–19 फाइनल में रचे ये कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क। वैभव अंडर–19 विश्व कप में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह बस ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, जिन्होंने इसी विश्व कप में 51 गेंद पर शतक जड़ा था। अंडर–19 वनडे विश्व कप का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच जारी है। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

हालांकि, जब भारत को चौथे ओवर में एरॉन जॉर्ज (9) के रूप में झटका लगा, तो ऐसा लगा कि म्हात्रे का फैसला गलत है, लेकिन इसके बाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे का कहर बरपा। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चौके–छक्कों की बरसात कर दी। इसी कड़ी

में 14 साल के वैभव ने 55 गेंदों में शतक पूरा किया और अंडर–19 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस मामले में चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद में 175 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। उन्हें लम्सडेन ने रियू के हाथों कैच कराया।

वैभव ने फरहान की गेंदों पर की छक्कों की बरसात

वैभव ने 15वें ओवर में स्पिनर फरहान अहमद की शुरुआती दो गेंदों पर दो छक्के लगाए। इस तरह मैच में उन्होंने पांच छक्के पूरे किए। वहीं, टूर्नामेंट में यह उनका 20वां छक्का रहा। इन दो छक्कों के साथ ही वैभव अंडर–19 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने 2022 अंडर–19 विश्व कप में डेवाल्ड ब्रेविस द्वारा लगाए गए कुल 18 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने इसके बाद 17वें ओवर में भी फरहान अहमद की लगातार चार गेंदों पर चार बाउंड्रीज लगाईं। इनमें तीन छक्के और एक चौका शामिल है।